



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 325 राँची, गुरुवार,

18 अप्रैल, 2019 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

08 मार्च, 2019 ई०।

विषय:- उग्रवादी घटनाओं अथवा राष्ट्र के रक्षार्थ कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल कर्मियों के पत्नी/आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने के संबंध में।

संख्या-18/विविध (07)10/17- 1352-- उग्रवादी घटनाओं अथवा राष्ट्र के रक्षार्थ कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल कर्मियों के पत्नी/आश्रितों के पुनर्वास हेतु विशेष सुविधा/राहत प्रदान करने के निमित्त राज्य सरकार द्वारा संकल्प सं०-2061, दिनांक-16.06.2004 निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प में राज्य निवासी शहीद केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के कर्मियों की पत्नी/आश्रित को निम्नांकित सुविधा प्रदान करने का प्रवधान है:-

- (i) रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी। यह सुविधा उसी व्यक्ति को दी जाएगी जिसका सत्यापन केन्द्रीय पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में किया जाएगा ।

- (ii) अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने के पूर्व यह आश्वस्त हो लिया जाएगा कि मृत कर्मों की पत्नी अथवा किसी आश्रित को केन्द्र सरकार/केन्द्रीय पुलिस बल द्वारा नौकरी नहीं दी गई हो ।
- (iii) अनुग्रह अनुदान का भुगतान बजट शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 800 अन्य व्यय 009 उग्रवादी घटनाओं में मारे गये पुलिसकर्मों/ग्रामीण पुलिस/गृह रक्षकों को विशेष अनुग्रह अनुदान मद से किया जाएगा।
- (iv) भुगतेय अनुग्रह अनुदान राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गृह विभाग, झारखण्ड राँची होंगे ।

2.(क) उक्त संकल्प को निर्गत हुये 13 वर्ष से अधिक की दीर्घ अवधि बीत चुकी है। विभागीय संकल्प संख्या-5193, दिनांक- 11.09.2018 द्वारा मिलिट्री आपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिक के पत्नी/आश्रित को रु. 2,00,000/- (दो लाख) से बढ़ाकर रु. 10,00,000/- (दस लाख) अनुग्रह अनुदान भुगतान का प्रावधान किया गया है। सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक बल कर्मों के कार्य की प्रकृति समान होती है दोनों ही बल के कर्मों देश की सीमा सुरक्षा/आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं तथा इसी दरम्यान वीरगति प्राप्त करते हैं। अतः दोनों ही बल के कर्मियों के आश्रित को देय अनुग्रह अनुदान में एकरूपता की आवश्यकता महसूस की गयी है। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त विभागीय संकल्प संख्या-2061, दिनांक-16.06.2004 की कंडिका-1 को आंशिक रूप से निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

“वीरगति प्राप्त अर्द्धसैनिक बल कर्मों के पत्नी/आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान के रूप में रु० 10,00,000/- (दस लाख) की राशि प्रदान किया जायेगा।”

(ख) विभागीय संकल्प संख्या-2061, दिनांक-16.06.2004 की कंडिका-1 के उपर्युक्त संशोधित प्रावधान दिनांक- 01.04.2018 के बाद घटित मामलों पर लागू होंगे।

(ग) उपर्युक्त संशोधन के पश्चात संशोधित नीति का निरूपण निम्नवत् होगा:-

उग्रवादी घटनाओं अथवा राष्ट्र की सीमा के रक्षार्थ कर्तव्य निर्वहनरत शहीद झारखण्ड निवासी केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मों की पत्नी/आश्रितों के पुनर्वास हेतु विशेष सुविधा/राहत प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतएव राज्य सरकार ने ऐसे शहीद की पत्नी/आश्रितों को निम्नलिखित विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी:-

- (i) उग्रवादी घटना अथवा राष्ट्र की सीमा के रक्षार्थ कर्तव्यनिर्वहनरत शहीद झारखण्ड निवासी केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल कर्मों की पत्नी/आश्रित को रु. 10,00,000/- (दस लाख) विशेष अनुग्रह अनुदान तथा पत्नी/आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उसी व्यक्ति को दी जाएगी जिसका सत्यापन केन्द्रीय पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में किया जाएगा।

- (ii) अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने के पूर्व यह आश्वस्त हो लिया जाएगा कि मृत कर्मों की पत्नी अथवा किसी आश्रित को केन्द्र सरकार /केन्द्रीय पुलिस बल द्वारा नौकरी नहीं दी गई हो।
- (iii) अनुग्रह अनुदान का भुगतान बजट शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-800-अन्य व्यय-009 उग्रवादी घटनाओं में मारे गये पुलिसकर्मों/ग्रामीण पुलिस/गृह रक्षकों को विशेष अनुग्रह अनुदान मद से किया जाएगा।
- (iv) भुगतेय अनुग्रह अनुदान राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गृह विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।
- (v) गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्रवाई के लिए नोडल विभाग होगा।

उपर्युक्त कंडिका-2 (ग) (i) के संशोधित प्रावधान दिनांक-01.04.2018 के बाद घटित मामलों पर लागू होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस०के०जी० रहाटे,
सरकार के प्रधान सचिव।
